

पाक में कोरोना वैक्सीन फाइजर को मंजूरी, 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का प्लान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन फाइजर को आपातकाल इस्टेमाल की मंजूरी दे दी गई है। अब यह 12 साल के बच्चों से लेकर खुल्गों तक की वैक्सीनेशन की योजना है। पाकिस्तान ने अभी तक 6 कोरोना वैक्सीन को इस्टेमाल के लिए मंजूरी दी है।

इसमें तीन की वैक्सीन-सीनोवेक्सीन और सोनोवेक्सीन की स्पूनिक वी व ब्रिटन की एस्ट्राजेनेका के साथ अब फाइजर भी शामिल हो गया है।

पाकिस्तान में फाइजर के कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्टेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहां के लोगों को इसकी खुराक मिल सकेंगे। इस्ट्राजेनेका बोर्ड ने 12 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को इस वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति दी है। इसके बाद पाकिस्तान में बच्चों को मिलने वाली यह पहली वैक्सीन है। अधिकारियों ने बताया, ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं समेत कम इम्युनिटी वाले लोगों की भी दी जा सकेगी। इसके अलावा हज पर जाने वाले 40 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को भी ये वैक्सीन साथ है। इस मसले पर तीसरी कोर्ट ने बोर्ड को कर्तव्यावाही की खुराक देने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान में फाइजर के कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्टेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहां के लोगों को इसकी खुराक मिल सकेंगे। इस्ट्राजेनेका बोर्ड ने 12 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को इस वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति दी है। इसके बाद पाकिस्तान में बच्चों को मिलने वाली यह पहली वैक्सीन है। अधिकारियों ने बताया, ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं समेत कम इम्युनिटी वाले लोगों की भी दी जा सकेगी। इसके अलावा हज पर जाने वाले 40 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को भी ये वैक्सीन साथ है। इस मसले पर तीसरी कोर्ट ने बोर्ड को कर्तव्यावाही की खुराक देने की अनुमति दी है।

भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने दी चेतावनी, ब्रिटेन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में

लंदन। ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक मशहूर वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में है और तीन चौथाई नए मामलों में कोरोना वायरस का वह वैरिएंट रहा है जो अब तक सामने आया है। साथ ही, उन्होंने प्रश्नांनंतरी वैरिएंट का नाम दिया है। जन द्वारा कोरोना की अपील की है। वैज्ञानिकों ने खबर दी कि सरकार के न्यू एंड इंविंग रेस्टेरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप (नवरेट) के सदस्य और कैबिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि गुरु ने कहा है कि वैरिएंट ने लॉकडाउन द्वारा नियंत्रित की गयी अपील को छोड़ दिया है। ब्रिटेन में लगातार पांचवें दिन कोरोना के 3,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। इससे पहले ब्रिटेन ने 12 अप्रैल के बाद यह अंकड़ा पार नहीं किया था। देश में कोरोना के कुल मामले 44,99,939 तक पहुंच गए हैं और अब तक 1,28,043 मरीजों ने जान गंवाई है। प्रो. गुरु ने कहा, फिल्हाल मार्गतों तो कम हैं, लेकिन सभी लहरों के अंकड़ों से ज्यादा होती है। बाद में वे विस्तोक हो जाती हैं, इसलिए वह अब अहम तरह है कि हमें यहां जो दिख रहा है वह शुरुआती लहर है।

डब्ल्यूएचओ को अब ज्यादा शक्तियां देने की तैयारी, भविष्य में किसी महामारी को काबू करना होगा आसान

जेनेवा। कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ज्यादा रहा विश्वस्त्र संगठन (डब्ल्यूएचओ) अपनी संरचना में बदलाव के सुझावों पर विचार के लिए तैयार हो गया है। संघर्षों से अपने विचारों से अपनी संरचना में बदलाव के लिए ये सुझाव व्यवस्थाएँ देखी जाएं जो भविष्य में अन्य महामारी के आने पर सक्षम तरीके से उसका सामान कर सकें।

गलवन घाटी में सैन्य झड़प पर सवाल उठाने वाले छाग की दुर्बिल में गिरपतारी के मामले की जांच करेगा चीन

बीजिंग। चीन ने कहा है कि गलवन घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में चीन के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया में सवाल उठाने वाले एक 19 वर्षीय छात्र की दुर्बिल में गिरपतारी के मामले की वह जांच करेगा। उसे चीन से अमेरिका जाने के गरमे में गिरपतारी के बाद में रिहा कर दिया गया था। दुर्बिल में गिरपतारी का स्थानीय निवासी है। उसे चीन से अमेरिका का स्थानीय निवासी है। उसे चीन से इस्टार्बुल (तुर्की) जाने के गरमे में संयुक्त अब अमेरिका के प्रशासन ने इस साल अप्रैल में गिरपतारी की व्यापारी से मदद मांगते हुए 20 मई को एक संदेश दिया। चीन से निकलने के बाद उसे दुर्बिल पुलिस ने गिरपतार कर दिया था। दुर्बिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसे तब गिरपतार किया गया था।

वैज्ञानिकों ने देखी वैक्सीन की तीसरी लहर के बारे में संगठन को ज्यादा शक्तियां देने की गयी है। संघर्षों और समझौतों की शर्तों में बदलाव के लिए वैक्सीन को लैपेट करें। अपनी वैक्सीन की संरचना में बदलाव के लिए ये सुझाव व्यवस्थाएँ देखी जाएं जो भविष्य में अन्य महामारी के आने पर सक्षम तरीके से उसका सामान कर सकें।

गलवन घाटी में सैन्य झड़प पर सवाल उठाने वाले छाग की दुर्बिल में गिरपतारी के मामले की जांच करेगा चीन

बीजिंग। चीन ने कहा है कि गलवन घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में चीन के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया में गिरपतारी के मामले की वह जांच करेगा। उसे चीन से अमेरिका जाने के गरमे में गिरपतारी के बाद में रिहा कर दिया गया था। दुर्बिल में गिरपतारी का स्थानीय निवासी है। उसे चीन से अमेरिका का स्थानीय निवासी है। उसे चीन से इस्टार्बुल (तुर्की) जाने के गरमे में संयुक्त अब अमेरिका के प्रशासन ने इस साल अप्रैल में गिरपतारी की व्यापारी से मदद मांगते हुए 20 मई को एक संदेश दिया। चीन से निकलने के बाद उसे दुर्बिल पुलिस ने गिरपतार कर दिया था। दुर्बिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उसे तब गिरपतार किया गया था।

पाक में कोरोना वैक्सीन फाइजर को मंजूरी, 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का प्लान

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन फाइजर को आपातकाल इस्टेमाल की मंजूरी दे दी गई है। अब यह 12 साल के बच्चों से लेकर खुल्गों तक की वैक्सीनेशन की योजना है। पाकिस्तान ने अभी तक 6 कोरोना वैक्सीन को इस्टेमाल के लिए मंजूरी दी है।

इसमें तीन की वैक्सीन-सीनोवेक्सीन और सोनोवेक्सीन की स्पूनिक वी व ब्रिटन की एस्ट्राजेनेका के साथ अब फाइजर की वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान में फाइजर के कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्टेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहां के लोगों को इसकी खुराक मिल सकेंगे। इस्ट्राजेनेका बोर्ड ने 12 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को इस वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति दी है। इसके बाद पाकिस्तान में बच्चों को मिलने वाली यह पहली वैक्सीन है। अधिकारियों ने बताया, ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं समेत कम इम्युनिटी वाले लोगों की भी दी जा सकेगी। इसके अलावा हज पर जाने वाले 40 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को भी ये वैक्सीन साथ है। इस मसले पर तीसरी कोर्ट ने बोर्ड को कर्तव्यावाही की खुराक देने की अनुमति दी है।

पाकिस्तान में फाइजर के कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्टेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यहां के लोगों को इसकी खुराक मिल सकेंगे। इस्ट्राजेनेका बोर्ड ने 12 साल की उम्र से अधिक के सभी लोगों को इस वैक्सीन की खुराक देने की अनुमति दी है। इसके बाद पाकिस्तान में बच्चों को मिलने वाली यह पहली वैक्सीन है। अधिकारियों ने बताया, ये वैक्सीन गर्भवती महिलाओं समेत कम इम्युनिटी वाले लोगों की भी दी जा सकेगी। इसके अलावा हज पर जाने वाले 40 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं को भी ये वैक्सीन साथ है। इस मसले पर तीसरी कोर्ट ने बोर्ड को कर्तव्यावाही की खुराक देने की अनुमति दी है।

कनाडा के एक स्कूल मिली सैकड़ों कब्र

दशकों पुराने बोर्डिंग स्कूल में मिले 215 बच्चों के शव, इनमें 3 साल के मासूम भी शामिल; दूड़ों बोले- ये इतिहास की शर्मनाक याद, ठोस कार्रवाई करेंगे

टोरंटो। कनाडा में दशकों पुराने एक बोर्डिंग स्कूल के परिसर में 215 अदिवासी समाजवाय के बच्चों की कब्र मिली है। इनमें तीन साल के मासूम बच्चों के शवों के अवशेष भी थी। इसपर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रॉटो ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि 'इनसे मेरा दिल तोड़ दिया'। वे हमारे इतिहास की शर्मनाक याद हैं। इनमें से एक है, जो 1890 से 1969 तक चलता था।

इसको बोर्डिंग स्कूल के सबसे बड़े बच्चों के बारे में बताया जाता है। इन शवों के बारे में पता लगाया गया है। कनाडा सरकार इस घटना पर मांग चुकी मापदण्ड

इससे पहले कनाडा सरकार ने 2008 में इस घटना के लिए माफी मांगी थी। फँस्टर नेशन के प्रमुख, टेमलप्स और क्रेपेसी ने कहा कि हम कोरिलप्स और इस मसले पर काम कर रहे हैं। जिन समुदाय के बच्चे इस स्कूल में पहले थे, उनके संपर्क में हैं। हम जल्द इसकी नीति जारी करेंगे। केम्लूप्स शहर की चीफ ऑफ कार्यालयी रोजने का कासिमिया का गहरा है। किंतु हम इसकी नीति जारी क

संपादकीय

सेवा के दावे पर कितना भरोसा

कोरोना के दूसरे भयावह दौर में राजनीति में अभी चिढ़ियों का दौर चल रहा है, 'लेटर बम' भेजे जा रहे हैं। इंटरनेट, वाट्सएप, टिकटोर और इंस्टाग्राम के साथ मोबाइल फोन के जरूरत में जब चिढ़ियां लिखना दूर की बात हो गई, तब राजनीतिक दलों को यह सबसे ताकतवर हथियार लग रहा है। राजनीतिक दल अपने विरोधी नेता को चिढ़ी लिख रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत देश के 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिढ़ी लिखी है और नौ सुझाव दिए हैं। उसमें बात सिर्फ कोरोना की नहीं है, कूछ और भी राजनीतिक सुझाव है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ी लिखी, तो उसका कड़ा-सा जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भेजा, फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लंबी चिढ़ी लिखी, तो उससे भी लंबा जवाब भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भेज दिया। उत्तर प्रदेश में मंत्री और एमएलए मुख्यमंत्री को चिढ़ी लिख रहे हैं। देश में कोरोना की इस दूसरी लहर में हरक दिन करीब चार लाख नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और करीब चार हजार लोगों की रोजाना मौत हो रही है। यह तो सरकारी आंकड़ा है, अनुमान इससे कई गुना ज्यादा मौत होने का है, वरना गंगा, यमुना और दूसरी नदियों में लाशें बहती न दिखतीं और न ही शमशानों व कब्रिस्तानों में मुर्दों के लिए जगह कम पड़ती। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों के लिए यह सबसे मजबूत हथियार है। सवाल है, क्या सबसे जरूरी काम इस वक्त सवाल पूछना भर है और वह भी तब, जब एक राज्य में कोई पार्टी सरकार में है, तो दूसरी विपक्ष में और हर जगह हाल यही है कि अपने गिरेबान में झांकें के बजाय हर कोई दूसरे पर अंगुली उठा रहा है। इस सबके बीच पिस रहा है आम आदमी, जिसके लिए अस्पताल में न बेड है, न ऑक्सीजन और न ही वेटिलेटर और बिना इलाज के मर जाए, तो शमशान-कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। जन-नाराजगी से पीछा छुड़ाने के लिए 'पॉजिटिविटी अनलिमिटेड डैपेंप' शुरू कर दिया गया है, पर क्या सिर्फ भाषणों और प्रवचनों से पॉजिटिविटी आ सकती है?

केंद्र और राज्यों में भौती सरकारों तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं ही कर रही हैं, हैरानी है कि 'राष्ट्र को प्रथम' और 'समाजसेवा के लिए राजनीति' में आए हमारे राजनीतिक दल, उनके नेता और कार्यकर्ता भी इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। साल 1950 में लोकतंत्र को अपनाने वाले इस देश में आज करीब 2,300 राजनीतिक दल हैं। इनमें चुनाव आयोग में सात राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर और 59 राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर पंजीकृत हैं। करीब 800 सांसद हैं, 4,120 विधायक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भाजपा के 1,300 और कांग्रेस के 870 विधायक हैं। इसके साथ ही, हजारों की तादाद में पार्षद, पंच और सरपंच हैं। राजनीतिक दलों के सदस्यों की तादाद देखी जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के 18 करोड़ सदस्य और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के करीब दो करोड़ सदस्य हैं। सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। कुल मिलाकर, 30 करोड़ से ज्यादा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता देश में हैं, यानी औसतन हर परिवार के पीछे एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिल सकता है और यदि देश के कुल ढाई करोड़ कोरोना मरीजों की तादाद मानें, तो हरेक मरीज की सेवा 14 राजनीतिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, पर क्या आपको तस्वीर ऐसी ही दिख रही है? क्या राजनेता व कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन पटना और बिहार में जब पूर्व यादव पीड़ितों के लिए काम करते दिखते हैं, तो उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दिलीप पाठे मरीजों को बिस्तर दिलाने की कोशिश में लगे हैं, तो उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। गुरुद्वारों के लोग लगे हैं, मस्जिदों, मंदिरों और चर्च में भी कुछ हड तक लगे हैं, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को सार्वजनिक करने वाले अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से सरकारें नहीं चूक रहीं। ये राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही वेंटिलेटर, बेड नहीं दे सकते, ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते, वैक्सीन की खुराक नहीं बना सकते, लेकिन उनके जमीन पर उतरने से इन्हाँ तो तय है कि दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी रुक जाती। विधायकों और सांसदों के सक्रिय होने पर अस्पताल बिस्तर भरे होने के झूठे आंकड़े नहीं दिखा पाते। लाखों के फर्जी बिल बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते।

राजनीतिक दल कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए कम से कम दो वक्त का भोजन उपलब्ध तो करा ही सकते थे और इतनी उम्मीद तो उनसे की ही जा सकती है कि वे मरने वालों के शवों का समानाजनक अंतिम संस्कार ही करवा दें। साल 2019 के आम चुनाव में भाजपा के 436 उम्मीदवारों में से 303 सांसद चुने गए, तो कांग्रेस के 421 उम्मीदवारों में से 52 चुनकर लोकसभा पहुंचे। इसी अनुपात में दूसरे दलों के भी उम्मीदवार हैं। सांसदों और विधायकों की बात छोड़िए, यदि ये हरे हुए लोग ही इस संकट काल में सेवा के लिए मैदान में उतर जाएं, तो हो सकता है कि अगली बार उनकी किस्मत बदल जाए। यहाँ जयपुर से कई बार भाजपा सांसद और विधायक रहे गिरधारी लाल भार्गव का जिक्र जरूरी लगता है। जब भार्गव विधायक से सांसद बने, तो उन्होंने जयपुर के शमशानों में गंगा में प्रवाहित होने के इंतजार में बरसों से पड़ी हजारों अस्थियों को प्रवाहित करने का संकल्प किया और वह हर शनिवार की रात रोडवेज की बस में बैठकर एक बोरा अस्थियां हरिद्वार लाते। अगले दिन संस्कार और समान के साथ उन्हें प्रवाहित कर देते। नतीजा जब एक बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह को उतार दिया, तब एक नारा चला, 'जिसका कोई न पूछे हाल, उसके संग गिरधारी लाल'। उस चुनाव का नतीजा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है और यह राजनेता के लिए सबक भी हो सकता है, गर वह सीखना चाहे।

जीवन का लाभ मिल

महामारी के लिए केंद्र को कठघरे में खड़ा कर रहे राज्यों को अपने अंदर भी झांकना होगा

कविवाच महामारी की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बाद ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वह धीरे-धीरे है सही, थम रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का आकलन है कि यह लहर कम ते हो रही है, पर इसके निष्क्रिय होने में समय लगेगा और इसीलिए तामाज़ शहरों में लॉकडाउन बरकरार रखने पड़ेगा। भारत जैसे विकासशील देशों में लॉकडाउन लंबे समय तक बरकरार रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है ध्यान रहे कि पिछले साल केविड महामारी ने अर्थिक तौर पर देश कर्कमर तोड़ कर रख दी थी। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी तब महामारी की दूसरी लहर आ गई जो कि अनुमान से बहुत तेज़ निकली। इस दूसरी लहर में सक्रमण इतना भयकर है कि पिछले साल जनता जो हौसला दिखा रही थी, वह इस बार नहीं दिखा पा रही। इस बास अन्य लोगों की तरह कारोबार जगत के भी कई लेपा संक्रमण की भौमि

विदेशी मीडिया को तो
यह भी बताना चाहिए कि
जब अमेरिका, इटली या
ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण
चरम पर था, तब क्या
उनके कैमरामैन-रिपोर्टर
कब्रिस्तानों का हाल बयान
कर रहे थे? देश का
मनोबल गिराने वाली
कवरेज से हमें सावधान
रहना होगा और देसी-
विदेशी मीडिया के शरारत
भरे एजेंडे को समझना
होगा। गिरा हुआ मनोबल
और राजनीतिक आरोप-
प्रत्यारोप हमें महामारी से
लड़ने में मदद नहीं करेगा।
इस समय जरूरत इसकी है
कि हम सकारात्मक रवैये
के साथ कोविड प्रोटोकॉल
को अपनाकर कोरोना से
निपटने और अर्थव्यवस्था
को पटरी पर लाने के लिए
मिलकर प्रयास करें।

A photograph showing a group of people, mostly men, gathered around several large oxygen cylinders. In the center, a man wearing a yellow t-shirt and dark pants is focused on adjusting a valve or fitting on a large, white, cylindrical oxygen tank. Other people are visible in the background, some wearing face masks. The setting appears to be an industrial or storage area for medical supplies.

महामारी की दूसरी लहर आई भी तो पहले जैसी होगी। शायद ही किसी ने सोचा हो कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग दस गुना बढ़ जाएगी और वह भी दस दिन के भीतर। भारत में ऐसी खतरनाक दूसरी लहर का अनुमान किसी अन्य देश का कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ या संगठन भी नहीं लगा सकता।

इस सबके बाद भी इसमें दो गय नहीं कि हमारा स्वास्थ्य ढाँचा पहले से ही चरमराया हुआ था। वह पहली लहर में ही नाकाफी साखित हुआ था। बीते एक साल में इस ढाँचे में जो परिवर्तन लाए जाने चाहिए थे, वे नहीं लाए गए। उभयाताल बैठक बनाना भी समस्या के एक पहलू पर ही जोर देना है, क्योंकि रैलियां तो विपक्षी नेता भी कर रहे थे। सच्चाई यह है कि बंगाल से अधिक संक्रमण दिल्ली, बैंगलुरु, गोवा आदि में फैला। यदि एक क्षण के लिए यह मान लें केंद्र समय पर नहीं चेता तो सबाल उठेगा कि आखिर राज्यों ने चेतने से क्यों इन्कार किया? कुंभ और बंगाल की रैलियों को मुझ बना रहे लोग यह न भूलें कि उन्हीं दिनों दिल्ली-मुंबई के बीच जमकर आवागमन हो रहा था और गोवा में हुड्डियां-पार्टियां मनाने वालों का तांता लगा हुआ था।

गोवा में संक्रमण गंभीर हुआ तो कुंभ नहाने या बंगाल की रैलियों में शामिल होने वालों के कारण नहीं। इसे विदेशी मीडिया का वह हिस्सा अवश्य समझें, जो दूसरी लहर से उजे छालात को लेकर भारत को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। विदेशी मीडिया को तो यह भी बताना चाहिए कि जब अमेरिका दूरल्ली या



याहू कि जब अपारका, इट्ला पा बिट्टेन में कोरोना संक्रमण चरम पर

लगाने की चिंता की गई। वह रही कि अस्पतालों को जो र दिए गए, वे बंद पड़े रहे। ब्रहुआ, जब प्रधानमंत्री त्रेयों को बार-बार आगाह ए यहाँ तक कह रहे थे कि नहर को तुरंत रोकना होगा, वह देशव्यापी रूप ले सकती थी कि अलावा केंद्र सरकार की ज्यों का दौरा भी कर रही थीं। है कि केंद्र को कठघरे में र रहे राज्यों को अपने अंदर रुक्ना होगा। केवल कुंभ पर उठाना या बंगाल में त्री की रैलियों को मुद्दा था, तब व्या उनके कैमरामैन-रिपोर्टर कबिस्तानों का हाल बयान कर रहे थे? देश का मनोबल गिराने वाली कवरेज से हमें सावधान रहना होगा और देसी-विदेशी मीडिया के शरारत भरे एजेंडे को समझना होगा। गिरा हुआ मनोबल और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप हमें महामारी से लड़ने में मदद नहीं करेगा। इस समय जरूरत इसकी है कि हम सकारात्मक रवैये के साथ कोविड प्रोटोकॉल को अपनाकर कोरोना से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलकर प्रयास करें।

फिर से आर्थिकी पर असर, विकास की धुरी पर घूमने वाला भारत आर्थिक दुष्पक्र में फंसकर उलझ सकता है

अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर विकाराल रूप लिए हुए हैं। यह जनता को घोर लापवाही का दुष्प्रणाम है अथवा फिर सरकार की नीतियों में कमी। फिलहाल कोई इसका जवाब देना नहीं चाह रहा है। बहरहाल सरकारें इससे निपटने के लिए अपने स्तर पर कहीं नाइट कफ्यू तो कहीं आशिक तो कहीं पूर्ण लॉकडाउन तक लगा रही हैं। साथ ही चिकित्सा संबंधी सुविधा बढ़ावे पर भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हैं कि सारी कोशिशें मानो बौनी होती जा रही हैं। दुनिया के देशों ने भी दिल खोलकर भारत को मदद पहुंचाई है, मगर देश अभी रहत नहीं महसूस कर रहा है। कोरोना वायरस का साइड इफेक्ट आप जनमानस के दैनिक कामकाज पर भी आसानी से देखा जा सकता है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कोरोना ने भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है और मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है। इसकी दूसरी लहर ने सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) का भी प्रभावित किया है।

गोरतलब है कि कोरोना को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से लाखों श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। दैनिक खर्च चलाने के लिए कईयों को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ी है। मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच देश में 23 करोड़ गरीब मजदुरों की कमाई कम हो गई। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि उस दौरान शहरी इलाकों में गरीबी 20 फोसद, जबकि ग्रामीण इलाकों में 15 प्रतिशत तक बढ़ी। जाहिर है कि इस दूसरी लहर के बाद देश में गरीबी की स्थिति और भयावह होगी। ध्यान रक्षित रूप से शहर तक रेजिस्ट्रेशन के बाद संक्रमण इन दिनों अमेरिकी रिसर्च एंड ऑफिस द्वारा आंकड़े पर विश्वास नहीं चलते भारत के मध्यम वर्ग गोरतलब है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक देश में मध्यम वर्ग करोड़ लोग थे अब यह देश में भी कम हो गई है। आय 50 डॉलर या उससे अधिक होने वाले देश में जबकि 1 डॉलर तक की कमाई अधिक होती है। खास यह भी है कि भारत के मध्यम वर्ग और गरीबी में भी अधिक देखा जा रही है। सालाह करीब छह करोड़ लोगों द्वारा शामिल हुए थे, मगर वर्ष 2020 में वृद्धि को एक साल में बिगड़े अर्थात् हालात द्वारा मई 2020 में अधिक देखा जा रही है। अर्थात् वर्ष 2020 में अधिक देखा जा रही है।

के 41 करोड़ से अधिक हैं जिन पर कोरोना का कहर बनकर टूटा है। यदि यूरिसिंच सेंटर के तो कोरोना महामारी के वर्ग भी खतरे में हैं। मध्यम वर्ग का आकार था, मगर कोरोना ने कई टरी कर दिया है। कोरोना की श्रेणी में करीब 10 लाख घटकर सात करोड़ स्तरवर्ग में जिनकी प्रतिदिन अधिक है वे उच्च श्रेणी दिन 10 डॉलर से 50 रुपये वाला मध्यम वर्ग में हैं जिनमें चीन की तुलना में संख्या में अधिक कमी वृद्धि होने की संभावना 2011 से 2019 के बीच मध्यम वर्ग की श्रेणी में ना ने एक दशक की इस घटा दिया। कोरोना से देखते हुए मोदी सरकार लाख करोड़ रुपये का पॉर्टफोलियो किया गया, मगर जिस सिलसिला जारी रहा। गरीबी में गुजर-बसर के काम-धंधे पहले ही बंद दानों के ताले अभी खुले ही मरी लहर आ गई। ऐसे में रोजगार का संकट आज भी बरकरार है। जाहिर है यह आर्थिक दृष्टक्रम बना रहेगा। पहली लहर में 14 करोड़ लोगों का पास बेरोजगार होना काफी कुछ बयां कर देता था दूसरी लहर भी इसमें कुछ बढ़ती ही करोड़ एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि कोरोना वायरस से इतनी बड़ी तबाही मचा दी। देश लगातार मुश्किलों को झेलता रहा। बावजूद इसके इससे निपटने के लिए एक समाज राष्ट्रीय नीति अभी तक सामने नहीं आई है? कोरोना को आए एक साल अधिक समय हो गया, अब दूसरी लहर उपान है, जबकि तीसरी लहर की संभावना भी व्यक्त जा चुकी है। यदि लहर पर लहर आती रहती तो इसका निस्तारण समय रहते न हुआ तो इसमें बड़े शक नहीं कि देश में गरीबों की तादाद और बढ़े भुखमरी और कुपोषण के आगोश में कर्स समाएंगे। तिहाजा विकास की धूरी पर धूमैने वाला भारत आर्थिक दृष्टक्रम में फंसकर उलझ सकता सुशासन की अवधारणा इसमें मददगार सार्वजनिक हो सकती है। अभिशासन के सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि सुशासन तब होता है जब सरकार अपने व्यय में मितव्ययिता बरतती अपनी शक्तियों को कम करती है, विनम्र भूमिका निभाती है और लोक सशक्तीकरण की ओर झुकती है। मौजूदा हालात में यह समय की मांग है। सरकार इस मामले में कितनी खरी उतरती है देखने वाली बात होगी। सरकार के अलावा जन को भी यह विचार करना है कि देश आखिर कोरोना के इस भवंतराज से कैसे बाहर निकले। उसे अनुशासन का परिचय देना होगा। अब समय रुदानों को होश में आ जाना चाहिए, ताकि सभ्यता संस्कृति और देश सभी को आसानी से पट्टी लाया जा सके।

सोशल मीडिया पर शिकंजा

लाल 25 फरवरी को घोषित हुई कानूनों को लागू करने के प्रति केंद्र सरकार और सोशल कंपनियां आमने-सामने हैं। पर तो इन कानूनों के कछु कछु को असंवैधानिक और के अधिकार का उल्लंघन है। इनके खिलाफ कोर्ट चला दिव्वटर ने अदालत की शरण ली है, लेकिन एक बयान दिया है कि वह इन कानूनों प्रावधानों में बदलाव को दिया करता रहेगा, जो कि की आजादी में बाधा नहीं है। अन्य सोशल मीडिया को ने कानून का पालन करने का जरूर जताई है, लेकिन वे नग-अलग तरीकों से यह दरही है कि इन कानूनों का करने में काफी मुश्किलें हैं। एक सरकार की बात है तो वह अपना कड़ा रुख कायम रखते दृसरे की अपत्तियों का जवाब दिया। उसका कहना गों के निजता के अधिकार भी सम्मान करती है, लेकिन अधिकार संरचने नहीं होता। कहना है कि एंड-टु-एंड गन भंग होने की जो बात प कह रहा है, वह आम के केस में वैसे भी लागू नहीं

कानून सिर्फ उन्हीं मामलों में लगा जाएगा, जहां देश की विदेश से संबंध और नक शांति व्यवस्था जैसे जुड़े होंगे। हालांकि सोशल का दुरुपयोग करने, इनके बाक न्यूज फैलाने की जितनी

शिकायतें आ रही हैं, उसके मद्देनजर इस पर विवेक का अंकुश लगाने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर ध्यान देने की बात यह भी है कि यह कानून सिर्फ सोशल मीडिया कंपनियों पर नहीं बल्कि मीडिया संस्थानों के डिजिटल संस्करणों पर भी लागू किया जाना है, जिनमें कॉमेंट सेक्षन होते हैं। इस पर अलग से भी काफी कुछ कहा जा चुका है कि मीडिया संस्थानों को इसमें शामिल करना न केवल अनावश्यक बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन अभी तक सरकार ने इन कानूनों में किसी तरह का बदलाव लाने का संकेत नहीं दिया है। दूसरी बात यह कि कौन सा कंटेंट आपत्तिजनक माना जाएगा, यह तय करने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है। जाहिर है, सोशल मीडिया कंपनियों को सभी कॉमेंट्स और संदेश अपने दावे में रखने होंगे। पता नहीं किस कॉमेंट को आपत्तिजनक मान लिया जाए, किन संदेशों की ओरेजिन पूछ दी जाए। यानी वॉट्सरेप मेसेज भी भेजने वाले और पाने वाले के बीच सीमित चीज नहीं रह जाएंगे। भले सरकार कह रही हो कि इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं मामलों में किया जाएगा, जिनमें और कोई उपाय न रह गया हो, लेकिन कोई उपाय रह गया है या नहीं, यह भी तो सरकार ही तय करेगी। पिछले दिनों सरकार ने सोशल मीडिया के खिलाफ जिस तरह का रुख दिखाया है, उससे संदेश बढ़ा है। बेहतर होगा कि सरकार इस मामले में बलपूर्वक आगे बढ़ने के बजाय बातचीत के जरिए संदेश दूर करते हुए आगे बढ़े।

तहस-नहस अर्थव्यवस्था और बर्बादी के कगार पर खड़े लोग एक ही सिक्के के दो पहल हैं

संकट की भयावहता को देखते हुए इतना बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन बिल्कुल उचित है। तहस-नहस होती अर्थव्यवस्था और बर्बादी के कगार पर खड़े लोग एक ही सिंध्के के दो पहलू हैं यह समझा जाना चाहिए कि तहस-नहस

होती अर्थव्यवस्था और बर्बादी के कगार पर खड़े लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को दूसरे से अलग करके देखा नहीं जा सकता। अगर हमारी नीतियां लोगों की सिमटती आपदनी और जाते रोजगार को वापस पूर्वस्थिति पर बहाल करने में कामयाब रहती हैं तो निस्संदेह अर्थव्यवस्था भी पठरी पर आती

आज देश कोरोना की दूसरी लहर के कारण युद्ध स्तरीय संकट के दौर से गुजर रहा है। इस स्थिति में ड्रूबती सांसों के बीच प्राणों को बचाना ही हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए, लेकिन इसके पश्चात बचा ली गई और बड़ी संख्या में उड़जड़ गई जिंदगियों को वापस पटरी पर लाने की अहमियत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोरोना के आने के पहले भी हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों की अपनी सबसे लंबी मंदी के दौर से गुजर रही थी। और फिर विरासती समस्याएं तो थी हीं, मसलन रोजगार सृजन की धीमी दर और कामगार तथा कार्यस्थलों की स्थिति में सुधार के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव। सच कहें तो बाँग्रे किसी सामाजिक सुरक्षा के कामकाजी वर्ग का एक बड़ा तबका किसी आकस्मिक संकट का सामना करने की स्थिति में नहीं था। इन सबके बावजूद धीमी रफ्तार से ही सही, देश का अर्थिक विकास तो हो रहा था। अर्थव्याप्रियों के आकलन के हिसाब से एक साल में करीब पांच करोड़ लोग न्यूनतम मजदूरी आय सीमा (375 रुपये प्रति दिन) के ऊपर आ जाते, लेकिन इस महामारी ने न केवल ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि इस आय सीमा से ऊपर के करोड़ों लोगों को नीचे पर ज्य इकोनॉ महीनों ने कह

भी धक्कल दिया।
आज जब देश की 98 फीसद आवादी फिर से किसी न किसी प्रकार की तालाबंदी के साए में आ चुकी है तो सरकार का पहला और सबसे बड़ा दायित्व पिछले साल की जमती की प्रगति को परिवर्तन तुलना मार्च-३ परिवर्तन हिस्साब



पर ज्यादा पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गत वर्ष अप्रैल और मई के महीनों में सबसे ज्यादा गरीब 20 फीसद परिवारों ने कुछ भी नहीं कमाया था। जबकि समृद्ध परिवारों की आमदनी में गिरावट महामारी पूर्व की तुलना में एक चौथाई से भी कम हुई थी। साथ ही मार्च-अक्टूबर के दौरान सबसे गरीब 10 फीसद परिवारों को 15,700 रुपये प्रति परिवार के द्विसाल से नकसान हुआ। यह रकम उनकी दो भी आमदनी पहले जैसी नहीं रही। बदतर हो गया हालात का एक अहम पहलू था लोगों की आय और खर्च की आई भारी गिरावट। परिवारों ने कम खाना खाकर उधार लेकर और परिसंपत्तियों को बेचकर इसकंट से जूझने की कोशिश की।

सरकारी राहत से संकट के सबसे भयानक रूपों से बचाव तो हुआ, लेकिन सहायता बैंगनी की पहुंच अधूरी रही और कुछ सबसे कमज़ोर वर्ग उनसे बचत रहे। जाहिर है कि देश



दुए नुकसान की भरपाई और दूसरी लहर के आशकित प्रभाव से बचाव के लिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी लाभार्थियों को भारत सरकार लगातार अन्न और दालें उपलब्ध कराने का बेहद जरूरी काम कर रही है। इस कार्यक्रम को कम से कम इस साल के अंत तक जारी रखने की जरूरत है। जून 2021 के बाद इसे बंद कर देने से हालात सभल नहीं पाएंगे और किए-कराए पर काफी हट तक पानी फिर जाने करने की आशंका रहेगी। यथासंभव अधिक से अधिक खस्ताहाल परिवारों को तीन महीने के लिए 5,000 रुपये नकद दिए जाने चाहिए। देखा जाए तो मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा कवच के लिए दिन काम करना चाहते थे। ऐसे में जरूरी है कि मररेगा की पात्रता में 150 दिनों का विस्तार हो और इसकी मजदूरी बढ़ाकर राज्य की न्यूनतम मजदूरी स्तर पर लाई जाए। इसके लिए इसके बजट को बढ़ाकर कम से कम 1.75 लाख करोड़ रुपये तक करना होगा। साथ ही सर्वाधिक प्रभावित जिलों में महिला श्रमिकों पर केंद्रित एक शाही रोजगार कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय योगदान में कम से कम 500 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए।

आंगनबाड़ी और आशा के 25 लाख कार्यकर्ताओं को छह महीने के लिए 30,000 रुपये (5,000 रुपये प्रति माह) का कोविड कठिनाई भत्ता मुहैया कराया जाना चाहिए। इन उपायों पर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे कोविड राहत पर कुल राजकोषीय परिव्यय दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.5 प्रतिशत हो जाएगा। संकेत के अनुसार ये दो प्रतिशतों के बीच विवरण दिये गये हैं।

रूप में एक महत्वपूर्ण भौमिका निर्भाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 तक 252 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस के कार्य संपन्न हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43 फीसद अधिक हैं। मनरेगा में पिछले वर्ष की तुलना में एक करोड़ अधिक परिवारों ने काम किया, लेकिन कई लोगों को काम चाहते हुए भी नहीं मिला। पिछले साल अप्रैल के बाद से उन ग्रामीणों में से केवल 55 प्रतिशत को ही काम दिया जा सका था, जो काम की मांग कर रहे थे। इसके अलावा जिन्हें काम मिला वे और अधिक



आदिपुरुष में रावण बनना नहीं था आसान

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपनी आने वाली फिल्म 'आदिपुरुष' में 'रावण' के किरदार को लेकर खास बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि 10 सिर वाले बड़े दानव और ताकतवर राजा का किरदार निभाना कितना मुश्किल भरा होने वाला है। 'फिल्म कंपैनियर' को दिया एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अपना एक बड़ा शोर किया है। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सैफ कहते हैं, 'फिल्म में पूरी तरह शैतान की तरह दिखेंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है इस किरदार के लिए हुक्म दिखेंगा, फिजिकली ही नहीं, बल्कि मैट्टली भी तैयार करना। यह किरदार काफी ताकतवर है और इसे करने में मजा आना वाला है।' सैफ कहते हैं, 'जब मैं रावण के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे यान आया कि रावण के किरदार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका घमड़। रावण को एक घमड़ी और अंहकारी राजा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक राष्ट्रकालीन राजा की टी-सीरीज कर रही है। फिल्म का निर्देशन अम रात कर रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान के अलावा 'बाहुबली' फेम एक्टर प्रभास 'राम' के रोल में नजर आएंगे, वहीं 'सीता' का किरदार कुतुंब सेनन निभाएंगी। साथ ही साथ 'प्यार का पंचानामा 2' फेम सनी सिंह 'लक्ष्मण' के किरदार में नजर आने वाले हैं। जहाँ तक सैफ अली खान के वर्कफ्रॉन्ट की बात करे सैफ अली खान के वर्कफ्रॉन्ट की बात करें तो उनके पास 'आदिपुरुष' के अलावा 'भूत पुलिस' और 'बंडी और बबली 2' जैसी फिल्में हैं।'

विकी कौशल की सरदार उद्धम सिंह भी ओटीटी पर!



सिनेमाघर को बंद हुए लंबा समय हो गया है और रिश्तों सामाचर नहीं में कितना समय लगाया, बताया नहीं जा सकता इसलिए फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को ऑटीटी पर बेचना ही सही समझ रहे हैं, भले ही मुनाफा कम हो। जब सामान खान जैसे सितारे की मौजी 'राधे' ऑटीटी पर दिखा दी गई है तो छोटे सितारों का क्या कहना। खबर है कि विकी कौशल की फिल्म 'सरदार उद्धम सिंह' ही अब ऑटीटी प्लेटफॉर्म को दी जा रही है। यह फिल्म अक्टोबर 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। फिर जनवरी 2021 में रिलीज करने की बात कही गई, तब भी कोरोना का प्रकाश कम नहीं हुआ था। कितना इंतजार करते? अब यह मूर्ती अगस्त में ऑटीटी पर सीधे दिखा दी जाएगी। नाम से ही जाहिर है कि यह मूर्ती क्रांतिकारी सरदार उद्धम सिंह की बायोपिक है जिसमें यह रोल विकी की गई टिप्पणी सीएमएस सचिवालय को

भारत में लोग कोविड से जूझ रहे थे, उस दौरान विदेश में शूटिंग ने उन्हें परेशान कर दिया

तेलुगु फिल्म 'थैंक यू' की शूटिंग के बाद हाल ही में इटली के मिलान से लोटी अभिनेत्री राशि खना ने खुलासा किया कि एक विदेशी स्थान पर शूटिंग ने उन्हें परेशान कर दिया। अभिनेत्री ने कहा है कि इटली में शूटिंग सुरक्षित थी क्योंकि देश में लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से प्रोटोकॉल का पालन किया। उन्होंने बताया कि 'हम महामारी के बीच में और मैं वहाँ (इटली) जाने से पहले डर गई थी। वहाँ एक बार, मुझे फैसास हुआ कि इटली में लोग मास्क पहनने के लिए बहुत जिम्मेदार थे, भले ही दूसरी लहर बीत गई हो। बहुत कम लोग शूटिंग कर रहे थे

हमें चालक दल में शामिल होना गया था और सभी साक्षात्कारियों वर्तानी गई थी।' राशि ने कहा, 'जब मैं वहाँ थी, भारत में दूसरी लहर तेज हो गई और मैं लगातार पढ़ रहा थी कि भारत में क्या हो रहा था। यह परेशान करने वाला था। यह बुरा लगा कि हमारा देश पीड़ित था और हम दूर थे। अब हम वापस आ गए हैं और हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। यह एक असहाय स्थिति है। हमें जो किया उसके लिए हमने शूटिंग की, लेकिन यह मानवीय रूप से परेशान कर रहा था। हम लगातार सोच रहे थे कि घर वापसी के बाद क्या होगा।'

अपने अभिनेत्री की शूरुआत शूजीत सरकार की 2013 की ही फिल्म 'मद्रास कैफ़े' से की, और बाद में 'टच येसी चुम्बू', 'वैकी मामा' और 'वल्ड फेमस लवर' जैसी हिट फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्म जगत में कदम रखा। इस बारे में बात करते हुए कि कैसे कोविड ने 'थैंक यू' की प्रोडक्शन टीम के लिए बाधाएं लाई, अभिनेत्री कहती है: 'ईमानदारी से, हमेशा समय पर खत्म करने का दबाव होता है लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम थी जिसने सब कुछ ध्यान में रखा था और उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। हम सभी शूटिंग खत्म करने के बारे में जानने में थे व्यापी किंतु हम भारतीय थे।'

वह आगे कहती है 'प्रोडक्शन टीम को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके अलावा हम वास्तव में सुरक्षित थे। ऐसे दिन थे जब हम दिन में 18 घंटे शूटिंग कर रहे थे क्योंकि हमारा पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि यह पहले जैसा नहीं था। महामारी जिसे आप विलासित में और कहीं भी शूट कर सकते थे। इस बार यह ज्यादा कठिन

था।' 'थैंक यू', 'वैकी
मामा' के बाद नामा
चैन्य के साथ
उनकी दूसरी
रिलीज होगी।

रणदीप हुड़डा को यूएन एंबेस्डर के पद से हटाया

अभिनेता रणदीप हुड़डा इन दिनों अपने एक पुराने वीडियो को लेकर चर्चा में बढ़े हुए हैं। वो ने जहाँ चाहीं वीडियो पर रणदीप को गिरपत्र करने की भाँग उठ रही तो वही अब अभिनेता के फैन्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल रणदीप हुड़डा को संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानरानी की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी सधि (सीएमएस) के राजदूत (एंबेस्डर) के पद से हटा दिया गया है। यह दिलाल दें कि रणदीप को फरवरी 2020 में तीन साल के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था।

सीएमएस सचिवालय को आपत्तिजनक लगी टिप्पणी
रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया, 'वीडियो में रणदीप हुड़डा ग्रामीण की जागीरी नाराजी है। रणदीप की वीडियो विलप वायरल होने के बाद लोगों में काफी नाराजी है।' और 'जाति सूचक कहकर कड़ी आपति जाता रहे हैं।'

आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जाती रही।

युविका वीडियो को आपत्तिजनक लगी जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट के बाद शहर थाने में युविका वीडियो को आ

पुरुष और महिला खिलाड़ियों की फैमिली भी जाएगी इंग्लैंड : यूके की सरकार ने दी इजाजत

मुंबई। इंग्लैंड के अहम दौरे पर जाने वाली भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के लिए रात की खबर है। यूके सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ के फैमिली मेंवर्स की भी इजाजत दे दी है। खिलाड़ी और उनके फैमिली मेंवर्स (जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं) पहले से मुंबई के एक होटल में क्राइस्टाइन हैं। यहाँ से वे 3 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। लंगे दूर और बायो बबल की सख्ती को देखते हुए BCCI की शुरू से योजना थी कि फैमिली मेंवर्स को साथ भेजा जाए, लेकिन इनके लिए यूके की सरकार की इजाजत जरूरी थी।

मुंबई से लंदन पहुंचेगी दोनों टीमें पुरुष और महिला टीमें फैमिली मेंवर्स के साथ 3 जून को चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई से लंदन के लिए रवाना होंगी। यहाँ से दोनों टीमों को साउथेम्पटन ले जाया जाएगा। साउथेम्पटन में खिलाड़ी और उनके परिवार पर ऐसे दोनों टीमों को जहाँ खुशी नहीं बहुत ही जाएगा। जापान ने वेटलिफ्टिंग के बाद अब तीरंदाजों की तैयारियों पर रोक लगा दी है।

पेरिस में 10 दिन के एकांतवास

में रहेंगे तीरंदाज

नीरज चोपड़ा को वीजा जारी करने के बाद फासीसी दूवावास ने तीरंदाजों

को भी वीजा जारी करने का फैसला लिया। पेरिस में 21 से 27 जून को होने वाले विश्व कप में महिला टीरंदाजों को

कोपा अमेरिका 2021: साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फरेशन ने 13 दिन पहले अर्जेंटीना से मेजबानी छीन ब्राजील को सौंपी

ब्राजील। कोपा अमेरिका अगले महीने ब्राजील में जून के मध्य आयोजित किया जाएगा। साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फरेशन की ओर से इसके संकेत दिए गए हैं। टूर्नामेंट के 2020 सीजन को कोरोना की वजह से एक साल के लिए टाल दिया गया था। टूर्नामेंट को इस साल 13 जून से 10 जूलाई के बीच अर्जेंटीना और कोलंबिया में संयुक्त रूप से किया जाना था।

टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना था। कोलंबिया में इसके आयोजन के विषेश में 20 मई को प्रदर्शन किया गया था। जिसके बाद कोलंबिया को सह मेजबानी से हटा दिया गया था। वहाँ अर्जेंटीना में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टूर्नामेंट से 13 दिन पहले मेजबानी ब्राजील को सौंप दी गई है। टूर्नामेंट अपने नियंत्रित समय के अनुसार ही होगा, हालांकि अपनी मैच के शेइयूल जारी नहीं किए गए हैं।

सागर मर्डर केस: ओलिंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की आर्म लाइसेंस होगी कैसिल

नई दिल्ली। जनवरी पहलवान सागर की हत्या में गिरफ्तार किए गए ओलिंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार के आर्म लाइसेंस डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और उनके PA को सागर के हत्या के आरोप में 23 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहाँ इस हत्या में शामिल चार अन्य लोगों की तत्वास्तर जारी है। सुशील अपनी क्राइम ब्रांच की रोटिणी कोर्ट ने सुशील की पुलिस कर्टडी 4 दिन और बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 7 दिनों की रियांड मार्गी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की ही कस्टडी पुलिस को दी। पुलिस ने सुशील पर जांच में सहयोग नहीं करेंगे का भी आरोप लगाया है।

दुबई में छुट्टियां मना रहे हैं मैटलिन्टन: 7 बार के फॉर्मूला-1 चैपियन अब स्टाइ-डाइविंग में आजमा रहे हैं

दुबई। रिकॉर्ड 7 बार के फॉर्मूला-1 चैपियन लुइस मैटलिन्टन इन दिनों दुबई में छुट्टियां मना रहे हैं। रेसिंग ट्रैक पर अपना जलवा बिखेरने वाले हैं मैटलिन्टन अब स्टाइ-डाइविंग में हाथ आजमा रहे हैं। उन्होंने दुबई में एक खतरनाक स्काइ-डाइविंग स्टंट भी किया। इसका बोलिंगो भी हैमिल्टन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिट्रिंग ड्राइवर हैं मैटलिन्टन अब 6 जून से होने वाले अंजरबैजान ग्रांप्री में नजर आयेंगे। हैमिल्टन ने ये स्काइ-डाइविंग दुबई में एक प्लेन से परफॉर्म किया। उन्होंने कहा- मैं पिछले काफी समय से स्काइ-डाइविंग सीख रखा था। ये मेरा फैंटेरेट टाइम पास है। मैंने पहली बार बैक साइड से इसे परफॉर्म किया। इसके बाद मैंने विंडटाल में प्रैक्टिस के लिए भी गया। इसके बारे में मैं अपने अगले पोस्ट में बताऊंगा।

यूरोपीय निशानेबाजी चैपियनशिप: मनु भाकर और राही सरनोबत ने बनाया एकसमान स्कोर

नई दिल्ली। टाक्कोंगो ओलिंपिक में भारत की पदक उम्मीद निशानेबाज राही सरनोबत और मनु भाकर ने यूरोपीय निशानेबाजी चैपियनशिप में 291 का समान स्कोर बनाया। स्पर्धा के न्यूनतम स्कोरकिंफेशन स्कोर

(एम्पीयूएस) वार्ष में सरनोबत और भाकर नियमित और एम्पीयूएस निशानेबाजों ने आठवें स्थान पर रहीं। इसमें 55 नियमित टीमों ने भाग लिया। पूर्व विश्व चैपियन आरोपी को स्टोरेंट्वेच 296 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहीं। रैपेड पायर रार्ड अभी खेला जाना है। 50 मीटर राइफल थीरीजन मिश्रित टीम वर्ग में भारत की अंजुम मैदागिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 19वें स्थान पर रहे।

यूरोपीय निशानेबाजी चैपियनशिप: जीटी4: तकनीकी खराबी ने सर्किट पॉल रिकॉर्ड में देसर अखिल रबिन्ड्र का खेल बिगाड़ा

बैंगलुरु। यूरोपीय निशानेबाजी चैपियनशिप 2021 में सर्किट पॉल रिकॉर्ड पर हुई रेस के पहले दौर में अखिल रविन्द्र को प्रदर्शन, गाड़ी में आयी तकनीकी खराबी के द्वारा बाधित हुआ। बैंगलुरु के 24 साल के रेसर अखिल, जो कि यूरोपीय निशानेबाजी चैपियनशिप में हिस्सा लेने वाले

इकलौते भारतीय हैं, उन्होंने सिल्वर केटरीर में 16वां स्थान हासिल किया। हूंगो कोडे और अखिल की जड़ी को मासमार्या के कारण रेस-1 में 16 लेप के बाद रिटायर होना पड़ा। इसके बाद AGS इवेंट्स रेसिंग टीम के लिए एस्टरन मार्टिन वैटेज जीटी4 चला रहे। अखिल ने रेस-2 में ड्रॉलिफाइंग रेस में 14वें स्थान (P-14) पर क्राइस्टाइन करने के बाद

संघाली। अखिल इकलौते पैशियाई भी हैं, जिन्होंने 2021 में प्रारंभिक एस्टरन मार्टिन रेसिंग ड्राइवर अंडीडीमी जाहानने में सफलता हासिल की। यह एक ऐसी उम्लबिंध है, जो उन्होंने लगातार तीसरे वर्ष हासिल की है।

ब्रॉलिफाइंग रेस में 14वें स्थान (P-14) पर क्राइस्टाइन करने के बाद

यैम इंवेंट में क्रालिफाई करना है। यही कारण है कि दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी और अंकिता भकत की अग्रवाई वाली महिला टीम को पांच जून को ही पेरिस विश्व रवाना कर दिया जाएगा। यह टीम को 23 दिनों के एकांतवास में रहना पड़ेगा। पुरुष तीरंदाज नौ जून को रवाना किए जाएंगे।

यैम इंवेंट में क्रालिफाई करना है। यही कारण है कि इस बार रीकर्व के साथ कॉउंटड तीरंदाजों को विश्व कप में खेलने भेजा जा रहा है। अतानु दास, प्रवीन जाधव, तस्णदीप रोयंग की टीम पहले ही ओलिंपिक के लिए क्रालिफाई कर चुकी है, जबकि दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में क्रालिफाई किया है।

तीरंदाजों के लिए झटका है टोक्यो में तैयारियों पर रोक

पेरिस विश्व कप के बाद तीरंदाजों को पांच जूलाई की टोक्यो के पास रिश्त कोरबेक सिटी ओलिंपिक की तैयारियों के लिए रवाना होना था। जापान रिश्त भारतीय दूतावास और तीरंदाजों की टोक्यो में अलग-अलग स्थानों पर तैयारियों की योजन बनाई थी। लेकिन पहले निर्णायन स्पॉर्ट्स साईंस यूनिवर्सिटी ने मीरावाई चानू को टोक्यो में तैयारियों से रोका।

अब कोरबेक सिटी ने तीरंदाजों की तैयारियों पर भी रोक लगा दी है। हालांकि साईं अभी भी प्रयास कर रही है कि किसी तरह मीरावाई और तीरंदाजों को टोक्यो में तैयारियों की अनुमति मिल जाए।

एशियाई मुक्केबाजी चैपियनशिप:

स्वर्ण पदक से चूके अमित पंधाल और शिव थापा, फाइनल में हारे

असम के इस मुक्केबाज को एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता मार्गित्या के बातासुख चिनजोरिंग ने 3-2 से हरा दिया। इसी के साथ थापा को भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

जूरी ने पंधाल की हार का रिव्यु दुकरा दिया

भारत ने पैशियाई मुक्केबाजी चैपियनशिप में गत चैपियन अमित पंधाल की 52 किलो वर्ग के फाइनल में हार का रिव्यु मांगा था, जिसे जूरी ने दुकरा दिया। पंधाल को अब रजत पदक से ही संतोष करना पड़ेगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने ट्रैटीट किया था, 'एप्सियाई फाइनल में अमित पंधाल की अप्रत्याशित हार के खिलाफ अपील करेगा।' महासंघ ने बाद में ट्रैटीट किया कि भारतीय टीम द्वारा दर्ज किया गया विश्व जूरी ने खारिज कर दिया।

बाटर रिव्यु व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैपियनशिप में गत चैपियन अमित पंधाल को पंधाल के मुक्केबाज के मुख्य कोडो को फैसले के 15 मिनट रिव्यु में उसे काम किया दर्ज करने का विश्व कोडो को